



Neutral Citation No. - 2026:AHC:30175

प्रतिवेद्य

सुरक्षित: 30.01.2026

पारित: 11.02.2026

आदेश से पहली अपील संख्या-1370 वर्ष 2024

सुभाषचंद्र गुप्ता ... अपीलकर्ता

बनाम

अजय कुमार शर्मा और अन्य... प्रतिपक्षीगण

पक्षगण के लिए उपस्थिति

अपीलकर्ताओं के लिए: श्री प्रमोद कुमार जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता, सैयद फहीम

अहमद

प्रतिपक्षियों के लिए: श्री देवीद कुमार सिंह, श्री प्रतीक राय

माननीय न्यायमूर्ति श्री संदीप जैन

1. धारा 104 सी.पी.सी. सपठित आदेश 43 नियम 1 (टी) के तहत प्रस्तुत अपील आदेश 43 नियम 1(टी) सहपठित धारा 104 सी.पी.सी. के अंतर्गत प्रतिपक्षी द्वारा दिनांक 23.5.2024 को पारित उस आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जो इन्दु द्विवेदी, अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 6, गाजियाबाद द्वारा विविध वाद संख्या 71 वर्ष 2019, सुभाष चन्द्र गुप्ता बनाम अजय कुमार शर्मा एवं अन्य में पारित किया गया था। उक्त आदेश द्वारा प्रतिवादियों के आवेदन संख्या 4-सी, जो आदेश 41 नियम 21 सी.पी.सी. के अंतर्गत दीवानी अपील संख्या 146 वर्ष 2011 में पारित एकपक्षीय निर्णय को वापस लिए जाने तथा अपील की गुण-दोष के आधार पर पुनः सुनवाई किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था, को अस्वीकार कर दिया गया है।

2. अपील स्वीकार की जाती है।

3. तथ्यात्मक मैट्रिक्स यह है कि वादी-प्रतिपक्षी संख्या-1 से 3 ने स्थायी निषेधाज्ञा और कब्जे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की राहत के लिए प्रतिपक्षी-अपीलकर्ता और सह-विपक्षी/प्रतिपक्षी फूल सिंह (मुकदमे के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई) के खिलाफ ओ.एस. संख्या-544 वर्ष 1997 दायर की थी, जिसे 18.8.2011 को अतिरिक्त दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) न्यायालय संख्या-2 गाजियाबाद द्वारा गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था, जिसे वादी द्वारा दीवानी अपील संख्या-146 वर्ष 2011 अजय कुमार शर्मा और अन्य बनाम दायर करके चुनौती दी गई थी गंगाराम और अन्य, जिला न्यायाधीश, गाजियाबाद के न्यायालय में, जिसे बाद में प्रवेश के बाद स्वीकार किया गया था, को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-6, गाजियाबाद को स्थानांतरित कर दिया गया।

सीए संख्या-146 वर्ष 2011 का प्रासंगिक कालक्रम

4. दीवानी अपील संख्या-146 वर्ष 2011 को 16.9.2011 को सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया था और उसके बाद, प्रतिपक्षियों को स्थगन आवेदन के निपटान के लिए 15.11.2011 को नोटिस जारी किया गया था और अपीलकर्ताओं को 7 दिनों के भीतर कदम उठाने का निर्देश दिया गया था। दिनांक 28-11-2011 को अपीलकर्ताओं ने समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से सेवा प्रदान करने के लिए आवेदन 19-सी2 के साथ पंजीकृत डाक के माध्यम से समन की तमीला को प्रभावित करने के लिए एक आवेदन 17-सी2 प्रस्तुत किया और न्यायालय ने उपरोक्त आवेदनों के निपटान के लिए 30-11-2011 को निर्धारित किया। 30.11.2011 को, वादी-अपीलकर्ताओं ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि वाद के लंबित रहने के दौरान विवादित संपत्ति विपक्षी-प्रतिपक्षी संख्या-4 सुभाष चंद गुप्ता को बेच दी गई है, क्योंकि कोई भी प्रतिपक्षी संख्या-1 से 3 की ओर से ब्याज नहीं ले रहा है और प्रतिपक्षी संख्या-4 जानबूझकर अदालत के समक्ष पेश नहीं हो रहा था, जबकि उसे अपील के बारे में पता था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रतिपक्षी विवादित संपत्ति को बेचने की जल्दी में था, क्योंकि कोई निषेधाज्ञा नहीं दी गई है। इस आधार पर, अपीलकर्ताओं द्वारा यह प्रार्थना की गई थी कि उन्हें प्रकाशन के माध्यम से प्रतिपक्षियों पर सेवा करने की अनुमति दी जाए, जिसे अपीलकर्ता अजय कुमार शर्मा (पेपर संख्या-20-सी) के एक हलफनामे द्वारा समर्थित किया गया था।

5. अपीलीय न्यायालय ने एक निष्कर्ष दर्ज किया कि पहले भी प्रतिपक्षियों को नोटिस भेजे गए थे, लेकिन उन पर सेवा प्रभावित नहीं की जा सकती थी, इसलिए, न्याय के हित में, अदालत ने 30.11.2011 को अपीलकर्ताओं को उनके खर्चों पर प्रकाशन के माध्यम से सेवा प्रभावित



करने की अनुमति दी, और आदेशित किया कि 4 दिनों के भीतर कदम उठाएं। तदनुसार अपीलकर्ता आवेदन 19-सी2 का निपटारा किया गया और अपीलीय अदालत ने सुनवाई के लिए 21.12.2011 की तारीख तय की।

6. अपीलीय अदालत ने 16.2.2012 को दर्ज किया कि प्रतिपक्षियों पर सेवा समाचार पत्र 21-सी2 में प्रकाशन द्वारा पर्याप्त थी, लेकिन उनमें से कोई भी इस तरह से मौजूद नहीं था, अदालत ने विपक्षी/प्रतिपक्षियों के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की और वादी-अपीलकर्ताओं की एकपक्षीय दलीलों को सुनने के लिए 29.2.2012 को निर्धारित किया।

7. अपीलीय अदालत ने 19.4.2012 को दर्ज किया कि प्रतिपक्षियों को भेजे गए पंजीकृत नोटिसों की देय पावती (एडी) अभिलेखों पर उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा, इस बात का कोई सबूत नहीं था कि अवर न्यायालय में पेश हो रहे प्रतिपक्षियों के अधिवक्ता पर नोटिस पर्याप्त था। अदालत ने यह भी कहा कि वादी के मुकदमे को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था, जिसे अपील में चुनौती दी गई है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह समीचीन था कि अपील की सुनवाई के नोटिस विचारण न्यायालय में पेश होने वाले विपक्षी/प्रतिपक्षियों के अधिवक्ता को भेजे जाएं, ताकि अपील को गुण-दोष के आधार पर सुना जा सके और इसके लिए अपीलकर्ताओं को एक सप्ताह के भीतर कदम उठाने का निर्देश दिया गया था।

8. अपीलीय न्यायालय ने 23.7.2012 को दर्ज किया कि प्रतिपक्षियों को फिर से नोटिस भेजे गए हैं, लेकिन वे उपस्थित नहीं हैं। न्यायालय ने अपील की एकपक्षीय सुनवाई के लिए दिनांक 13-08-2012 की तारीख तय की। अंततः, अपीलीय अदालत ने 6.7.2019 को अपीलकर्ताओं की दलीलें सुनीं और फैसला सुनाने के लिए 17.7.2019 की तारीख तय की। 17.7.2019 को, दीवानी अपील को एकपक्षीय रूप से अनुमति दी गई थी और परिणामस्वरूप, ओ.एस. संख्या-544 वर्ष 1997 में पारित डिक्री को रद्द कर दिया गया था और वादी के मुकदमे को खारिज कर दिया गया था। विपक्षी/प्रतिपक्षियों को 3 महीने के भीतर विवादित संपत्ति का कब्जा अपीलकर्ताओं को सौंपने का निर्देश दिया गया था, जिसमें विफल रहने पर, अपीलकर्ताओं को अदालत के माध्यम से कानून के अनुसार इसे प्राप्त करने का हकदार माना गया।

विविध प्रकरण संख्या-71 वर्ष 2019 की कार्यवाही

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. यह मामला प्रतिपक्षी-अपीलकर्ता सुभाष चंद गुप्ता द्वारा 14.8.2019 को 2011 के सीए 146 में दिनांक 17.7.2019 के एकपक्षीय निर्णय को याद करने के लिए धारा 151 सी.पी.सी. सपठित आदेश 41 नियम 21 के तहत स्थापित किया गया था, इस कथन के साथ कि 2.8.2019 को उसे अपने आवास पर एक लिफाफा मिला था, लेकिन उस समय, वह कुछ आवश्यक कार्य के लिए देहरादून में था, इस प्रकार, वह लिफाफा नहीं देख पा रहा था, लेकिन 8.8.2019 को लौटने के बाद, जब उसने लिफाफा खोला, तो उसे पता चला कि वादी/अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में धारा 148-ए सी.पी.सी. के तहत एक कैविएट दायर की थी। यह भी कहा गया कि लिफाफे की सामग्री को देखने से उन्हें पता चला कि सीए 146 वर्ष 2011 में कुछ आदेश पारित किया गया है, जिसके संबंध में, वादी ने उच्च न्यायालय में एक कैविएट दायर की है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि 9.8.2019 को उन्होंने अपने अधिवक्ता ब्रह्म प्रकाश निर्भया से संपर्क किया और उन्हें लिफाफा दिखाया, फिर उनके अधिवक्ता ने 13.8.2019 को अपील के अभिलेखों का निरीक्षण किया और तब उन्हें पता चला कि उपरोक्त अपील पर एकपक्षीय निर्णय लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि उपरोक्त फाइल के निरीक्षण से, उन्हें पता चला कि उन पर कभी भी कोई पंजीकृत नोटिस या समन नहीं दिया गया था और एक समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से उन पर पर्याप्त सेवा मानी गई थी, जिसे उनके द्वारा पढ़ा नहीं गया था, इस तरह, उन्हें अपील के बारे में कभी पता नहीं चला। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अधिवक्ता पर अपील का कोई नोटिस भी नहीं था, जो अवर न्यायालय में उनकी ओर से पेश हो रहे थे। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अपील की एकपक्षीय सुनवाई के कारण, उन्हें गंभीर नुकसान हुआ है और इस तरह, अपील में पारित दिनांक 17.7.2019 के आदेश को वापस लिया जाए और अपील को सुनने के बाद गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाए। उपरोक्त आवेदन के साथ प्रतिपक्षी सुभाष चंद गुप्ता का एक हलफनामा प्रस्तुत किया गया था।

10. अपीलकर्ता के उपरोक्त आवेदन का वादी द्वारा इस आधार पर विरोध किया गया था कि ओ.एस. 544 वर्ष 1997 में भी अपना लिखित बयान दाखिल करने के बाद, प्रतिपक्षी/अपीलकर्ता सुभाष चंद गुप्ता मुकदमे के निपटान में देरी करने के लिए अनुपस्थित रहे, जिसका उल्लेख विचारण न्यायालय के फैसले में भी किया गया था। वादी द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रतिपक्षी/अपीलकर्ता जानबूझकर अपील में उपस्थित होने में विफल रहा, जबकि वह अपील से पूरी तरह अवगत था। यह स्वीकार किया गया था कि प्रतिपक्षी पर स्थानीय समाचार पत्र में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रकाशन के माध्यम से सेवा प्रभावित की गई थी, जो अपील के अभिलेखों पर पेपर संख्या-21-सी था। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि चूंकि प्रतिपक्षी अपील के बारे में पूरी तरह से जानता था, इसलिए आवेदन कानूनी रूप से बनाए रखने योग्य नहीं था, जिसे खारिज किया जाना था। आपत्ति के समर्थन में वादी अजय कुमार शर्मा का हलफनामा दायर किया गया था।

11. अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 23.5.2024 के आक्षेपित आदेश द्वारा आदेश 41 नियम 21 सी.पी.सी. के तहत प्रतिपक्षी/अपीलकर्ता आवेदन संख्या-4-सी को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि यह प्रतिपक्षी का मामला नहीं है कि समन और नोटिस उसके गलत पते पर भेजे गए थे क्योंकि प्रतिपक्षी द्वारा अपने आवेदन में उल्लिखित पता एक ही था, जैसा कि अपील के वादपत्र और ज्ञापन में उल्लेख किया गया था। अदालत द्वारा आगे यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह माना जा सकता है कि प्रतिपक्षी को भेजे गए नोटिस और समन उसे विधिवत तामील किए गए थे। इसके अलावा, समाचार पत्र में प्रकाशन भी प्रभावित किया गया था। अदालत की राय थी कि चूंकि प्रतिपक्षी ने कैविएट की प्रति दाखिल नहीं की है, इसलिए कैविएट के माध्यम से ज्ञान का उसका दावा विश्वसनीय नहीं है। अंततः, प्रतिपक्षी के आचरण के आधार पर न्यायालय ने यह मान लिया कि उसे समन और प्रकाशन के माध्यम से अपील की सूचना मिल रही थी, लेकिन वह जानबूझकर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहा, लेकिन एकपक्षीय डिक्री पारित होने के तुरंत बाद, एक महीने के भीतर अदालत के समक्ष पेश हुआ, जिससे पता चलता है कि उसे अपील की पूरी जानकारी थी। लेकिन वह जानबूझकर उपस्थित होने में विफल रहा। उपरोक्त आवेदन की अस्वीकृति से व्यथित होकर, प्रतिपक्षी ने आदेश 43 नियम 1 (टी) सी.पी.सी. के तहत यह प्रस्तुत अपील दायर की है।

पक्षों के अधिवक्ता की प्रस्तुतियाँ

12. प्रतिपक्षी/अपीलकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रमोद जैन ने प्रस्तुत किया कि यह मानने के लिए अभिलेखों पर कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि प्रतिपक्षी/अपीलकर्ता को कभी भी पंजीकृत नोटिस भेजे गए थे, जिन्हें उनके द्वारा स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया था; कि प्रक्रिया सर्वर के माध्यम से भेजे गए सम्मन को अपीलकर्ता द्वारा स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया था; अपीलकर्ता प्रोसेस सर्वर या पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजे गए समन की तमीला से बच रहा था, इस प्रकार, उपरोक्त साक्ष्य के बिना, अपीलीय अदालत स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से अपीलकर्ता पर सेवा को प्रभावित करने का आदेश नहीं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दे सकती थी। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एक समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से प्रतिस्थापित सेवा केवल तभी प्रभावित की जा सकती है, जब अदालत की राय है कि प्रतिपक्षी जानबूझकर सामान्य मोड के माध्यम से सेवा से बच रहा है। अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आमतौर पर प्रोसेस सर्वर के माध्यम से कम से कम दो या तीन बार पंजीकृत नोटिस या समन विपक्षी/प्रतिपक्षी को भेजे जाते हैं, और जब यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिपक्षी सेवा से बचने की कोशिश कर रहा था, तभी यह आदेश दिया जाता है कि स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से प्रतिस्थापित सेवा को प्रभावित किया जाए।

13. अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि इस मामले में प्रतिपक्षी/अपीलकर्ता दिल्ली का निवासी था, लेकिन जिस समाचार पत्र में समन प्रकाशित किया गया था, उसका दिल्ली में कोई प्रसार नहीं था, जिसे अपीलकर्ता द्वारा नहीं पढ़ा गया था, इस प्रकार, प्रकाशन के बाद भी, अपीलकर्ता अपील के बारे में अनजान रहा और इसलिए, अदालत के समक्ष पेश नहीं हो सका। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलीय अदालत ने अपीलकर्ता के अधिवक्ता पर सेवा को प्रभावित करने की भी कोशिश की, जो विचारण न्यायालय में पेश हुए, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अधिवक्ता को विधिवत नोटिस दिया गया था। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चूंकि विचारण न्यायालय में अपीलकर्ता या उसके अधिवक्ता को नोटिस या समन की कोई सेवा नहीं दी गई थी, इसलिए अपील की सुनवाई के दौरान कोई भी अपीलीय अदालत के समक्ष पेश नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी, अपीलीय अदालत ने अपीलकर्ता के आचरण से यह मान लिया है कि वह अपील की कार्यवाही से पूरी तरह से अवगत था और वह जानबूझकर अपीलीय अदालत के सामने पेश नहीं हुआ। जो एक विकृत खोज है। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि आदेश V सी.पी.सी. के अनिवार्य प्रावधानों का पालन किए बिना, प्रतिपक्षी पर पर्याप्त सेवा मान ली गई है, जो अवैध है। अपने तर्क के समर्थन में अधिवक्ता ने मामले के कानून पर भरोसा किया है: -

(1)ओम प्रकाश बनाम प्रकाश चंद और अन्य तटस्थ उद्धरण 2004 एएचसी

106 (डीबी)

(2)के. राजा बनाम वी.प्रभाकर, न्यूट्रल साइटेशन 2024 केएचसी 49086

(कर्नाटक)



(3) तेहारून चंद बनाम सूरजमुल नागरमुल ए.आई.आर. 1984 कैल 82 (डीबी)

(4) श्रीमती पायल अशोक कुमार जिंदल बनाम कैप्टन अशोक कुमार जिंदल
(1992)3 एस.सी.सी. 116

(5) श्रीमती यलुवा बनाम श्रीमती शांताव्वा (1997) 11 एस.सी.सी. 159.

14. इसके विपरीत, वादी-प्रतिपक्षियों के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिपक्षी/अपीलकर्ता अपील की कार्यवाही से अच्छी तरह वाकिफ था, जो अपील के निपटान में देरी करने के लिए जानबूझकर अपीलीय अदालत के समक्ष पेश नहीं हुआ, इस प्रकार, अपीलीय अदालत ने उसके वापस बुलाने के आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया है। अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता को विधिवत नोटिस और समन भेजे गए थे, और स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से उस पर प्रतिस्थापित सेवा भी प्रभावित की गई थी, जो आदेश V सी.पी.सी. के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार था, इस प्रकार, अपीलीय अदालत द्वारा अपील की सुनवाई और निर्णय लेने में कोई अवैधता नहीं की गई थी। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलीय अदालत ने अपीलकर्ता के आचरण को सही ढंग से नोट किया है, जिसने अपील के लंबित रहने के दौरान जानबूझकर अपीलीय अदालत के समक्ष पेश होने से परहेज किया था। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि प्रतिपक्षी के अधिवक्ता को भी नोटिस दिया गया था, जो विचारण न्यायालय के समक्ष मूल मुकदमे में पेश हो रहे थे, लेकिन अधिवक्ता भी जानबूझकर अपीलीय अदालत के समक्ष पेश होने में विफल रहे। इन प्रस्तुतियों के साथ, यह प्रार्थना की गई थी कि अपील गुणहीन है और इसे खारिज कर दिया जाए।

15. मैंने दोनों पक्षों की सलाह सुनी है और आक्षेपित आदेश के साथ-साथ अवर न्यायालय के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

16. पक्षों के अधिवक्ता की प्रस्तुतियों और अभिलेखों के अवलोकन के आधार पर, इस अपील में निर्धारण के लिए निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं: -

(i) क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय प्रतिपक्षी-प्रतिपक्षियों पर प्रतिस्थापित सेवा को प्रभावित करने के लिए वादी-अपीलकर्ता के आवेदन की अनुमति देने में उचित था?

(ii) क्या इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अभिलेखों पर पर्याप्त सामग्री थी कि विपक्षी-प्रतिपक्षी सेवा से बच रहे थे और वे जानबूझकर अपील में उपस्थित नहीं हो रहे थे?



(iii) क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय प्रतिपक्षियों-प्रतिपक्षियों को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना एकपक्षीय अपील की सुनवाई करना न्यायोचित था?

प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान

17. मुद्दे में विवाद की मूल्यांकन करने के लिए, यह उचित होगा कि आदेश V सी.पी.सी. के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार किया जाए। सी.पी.सी. के आदेश V नियम 9, 12, 15, 17, 19, 20, 21 में उल्लिखित प्रासंगिक प्रावधान निम्नानुसार हैं: -

9. न्यायालय द्वारा समन का वितरण "(1) जहां प्रतिपक्षी उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर रहता है जिसमें मुकदमा स्थापित किया गया है, या उस अधिकार क्षेत्र के भीतर रहने वाला एक एजेंट है जिसे सम्मन की सेवा स्वीकार करने का अधिकार है, सम्मन तब तक होगा, जब तक कि

न्यायालय अन्यथा निर्देश देता है, वितरित किया जाए या तो उचित अधिकारी को उसके या उसके अधीनस्थों में से एक द्वारा सेवा प्रदान करने के लिए या ऐसी कूरियर सेवाओं के लिए भेजा जाए जो न्यायालय द्वारा अनुमोदित हैं।

(2) समुचित अधिकारी उस न्यायालय का अधिकारी हो सकेगा जिसमें वाद स्थापित किया गया है, और जहां वह ऐसा अधिकारी है, वहां उसे समन उस रीति से भेजा जा सकेगा जो न्यायालय निदेश दे।

(3) समन की तमीलाएं पंजीकृत डाक पावती देय द्वारा उसकी एक प्रति वितरित या प्रसारित करके की जा सकती हैं, जो प्रतिपक्षी या उसके एजेंट को सेवा स्वीकार करने के लिए सशक्त है या स्पीड पोस्ट द्वारा या ऐसी कूरियर सेवाओं द्वारा जो उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित हैं या उप-नियम (1) में निर्दिष्ट न्यायालय द्वारा अनुमोदित हैं या दस्तावेजों के प्रसारण के किसी अन्य माध्यम (फैक्स संदेश या इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा सहित) द्वारा प्रदान की जा सकती हैं। उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम:

बशर्ते कि इस उप-नियम के तहत सम्मन की सेवा वादी के खर्च पर की जाएगी।

(4) उप-नियम (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, जहां एक प्रतिपक्षी उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहता है जिसमें वाद स्थापित किया गया है, और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय निर्देश देता है कि उस प्रतिपक्षी पर समन की तमीला ऐसे समन की तमीला द्वारा की जा सकती है जैसा कि उप-नियम (3) में निर्दिष्ट है (देय पंजीकृत डाक पावती को छोड़कर), नियम 21 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

(5) जब प्रतिपक्षी या उसके एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित होने की कथित तौर पर एक पावती या कोई अन्य रसीद न्यायालय या डाक लेख जिसमें सम्मन शामिल है, न्यायालय द्वारा वापस प्राप्त किया जाता है, तो एक डाक कर्मचारी द्वारा या कूरियर सेवा द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा इस आशय के समर्थन के साथ वापस प्राप्त किया जाता है कि प्रतिपक्षी या उसके एजेंट ने डाक लेख की डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया था समन या उप-नियम (3) में निर्दिष्ट किसी अन्य माध्यम से समन स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जब उसे प्रस्तुत या प्रेषित किया जाता है, तो समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषणा करेगा कि सम्मन प्रतिपक्षी को विधिवत तामील किया गया था:

बशर्ते कि जहां समन को ठीक से संबोधित किया गया था, पूर्व-भुगतान किया गया था और पंजीकृत डाक पावती द्वारा विधिवत भेजा गया था, इस उप-नियम में निर्दिष्ट घोषणा इस तथ्य के बावजूद की जाएगी कि पावती खो गई है या गुम हो गई है, या किसी अन्य कारण से, समन जारी करने की तारीख से तीस दिनों के भीतर न्यायालय को प्राप्त नहीं हुई है।

(6) उच्च न्यायालय या जिला न्यायाधीश, जैसा भी मामला हो, कूरियर एजेंसियों का एक पैनल तैयार करेगा

उप-नियम (1) के उद्देश्य।

12. व्यावहारिक होने पर प्रतिपक्षी पर व्यक्तिगत रूप से या उसके एजेंट पर सेवा होनी चाहिए। -जहां भी यह व्यावहारिक है, प्रतिपक्षी पर व्यक्तिगत रूप से सेवा की जाएगी, जब तक कि उसके पास सेवा स्वीकार करने का अधिकार न हो, इस मामले में ऐसे एजेंट पर सेवा पर्याप्त होगी।

15. जहां प्रतिपक्षी के परिवार के किसी वयस्क सदस्य पर सेवा हो सकती है। - जहां किसी भी मुकदमे में प्रतिपक्षी उस समय अपने निवास से अनुपस्थित होता है जब उसके



निवास पर सम्मन की सेवा को प्रभावित करने की मांग की जाती है और उचित समय के भीतर उसके निवास पर उसके पाए जाने की कोई संभावना नहीं है और उसके पास अपनी ओर से सम्मन की सेवा स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त करने वाला कोई एजेंट नहीं है, परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य पर सेवा की जा सकती है, चाहे वह पुरुष हो या महिला, जो उसके साथ रह रहा हो।

खुलासा: "एक नौकर इस नियम के अर्थ के भीतर परिवार का सदस्य नहीं है।

17. प्रक्रिया जब प्रतिपक्षी सेवा स्वीकार करने से इनकार करता है, या नहीं पाया जा सकता है- जहां प्रतिपक्षी या उसके एजेंट या पूर्वोक्त के रूप में इस तरह के अन्य व्यक्ति पावती पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, या जहां सेवारत अधिकारी, सभी उचित और उचित परिश्रम का उपयोग करने के बाद, प्रतिपक्षी को नहीं ढूंढ सकता है, जो उस समय अपने निवास से अनुपस्थित है, जब उसके निवास पर उस पर सेवा करने की मांग की जाती है और उसके पाए जाने की कोई संभावना नहीं है एक उचित समय के भीतर निवास पर और उसकी ओर से सम्मन की सेवा स्वीकार करने के लिए सशक्त कोई एजेंट नहीं है, और न ही कोई अन्य व्यक्ति जिस पर सेवा की जा सकती है, सेवारत अधिकारी बाहरी दरवाजे या घर के किसी अन्य विशिष्ट हिस्से पर सम्मन की एक प्रति चिपका देगा जिसमें प्रतिपक्षी आमतौर पर रहता है या व्यवसाय करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है, और फिर मूल को उस न्यायालय को वापस कर देगा जहां से इसे जारी किया गया था, उस पर एक रिपोर्ट का समर्थन किया गया था या उसमें संलग्न किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उसने प्रति चिपका दी है, जिन परिस्थितियों में उसने ऐसा किया था, और उस व्यक्ति का नाम और पता (यदि कोई हो) जिसके द्वारा घर की पहचान की गई थी और जिसकी उपस्थिति में प्रति चिपकाई गई थी।

19. सेवारत अधिकारी की परीक्षा-जहां नियम 17 के तहत एक सम्मन वापस किया जाता है, न्यायालय करेगा, यदि उस नियम के तहत रिटर्न को सेवारत अधिकारी के शपथ पत्र द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है, और यदि यह सत्यापित किया गया है, तो शपथ पर सेवारत अधिकारी की जांच कर सकता है, या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उसकी जांच करवा सकता है, अपनी कार्यवाही को छूते हुए, और इस मामले में आगे की



जांच कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे; और या तो घोषणा करेगा कि सम्मन विधिवत तामील किया गया है या ऐसी सेवा का आदेश देगा जो वह उचित समझता है।

20. प्रतिस्थापित सेवा- (1) जहां न्यायालय संतुष्ट है कि यह मानने का कारण है कि प्रतिपक्षी सेवा से बचने के उद्देश्य से रास्ते से बाहर रख रहा है, या किसी अन्य कारण से समन को सामान्य तरीके से तामील नहीं किया जा सकता है, न्यायालय न्यायालय में किसी विशिष्ट स्थान पर उसकी एक प्रति चिपकाकर सम्मन तामील करने का आदेश देगा, और घर के कुछ विशिष्ट हिस्से (यदि कोई हो) पर भी जिसमें प्रतिपक्षी को अंतिम रूप से रहने या व्यवसाय करने या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करने के लिए जाना जाता है, या इस तरह के अन्य तरीके से जैसा कि न्यायालय उचित समझता है।

(1क) जहां उपनियम (1) के अधीन कार्य करने वाला न्यायालय किसी समाचार पत्र में विज्ञापन देकर सेवा का आदेश देता है, वहां समाचार पत्र उस इलाके में प्रसारित होने वाला दैनिक समाचार पत्र होगा जिसमें प्रतिपक्षी को अंतिम बार वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करने के लिए जाना जाता है, व्यवसाय करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है।

(2) प्रतिस्थापित सेवा का प्रभाव-- न्यायालय के आदेश द्वारा प्रतिस्थापित सेवा उतनी ही प्रभावी होगी जैसे कि वह प्रतिपक्षी पर व्यक्तिगत रूप से की गई हो।

(3) जहां सेवा प्रतिस्थापित की जाती है, वहां उपस्थित होने का समय नियत किया जाना है- जहां सेवा को न्यायालय के आदेश द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, न्यायालय प्रतिपक्षी की उपस्थिति के लिए ऐसा समय नियत करेगा, जैसा भी मामला हो सकता है।

21. सम्मन की सेवा जहां प्रतिपक्षी किसी अन्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रहता है-

जिस न्यायालय द्वारा समन जारी किया जाता है, वह समन, चाहे राज्य के भीतर तामील किया जाना हो अथवा राज्य के बाहर, अपने किसी अधिकारी के माध्यम से अथवा डाक द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किसी कूरियर सेवा के माध्यम से, अथवा फैक्स संदेश द्वारा, अथवा इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा के माध्यम से, अथवा उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों



के अधीन उपबंधित किसी अन्य माध्यम से, उस स्थान पर अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय (उच्च न्यायालय से भिन्न), जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर प्रतिपक्षी निवास करता हो, को प्रेषित किया जा सकता है।

न्याय निर्णयज विधि को संदर्भित और विचार किया गया

18. ओम प्रकाश (उपरोक्त) में इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने आदेश V नियम 20 सी.पी.सी. पर विचार करने के बाद निम्नानुसार निर्णय दिया: -

"प्रतिस्थापित सेवा की अनुमति है, बशर्ते कि अदालतें पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद कारणों को दर्ज करें कि सेवा को सामान्य तरीके से प्रभावित नहीं किया जा सकता है और इसे अधिकार के मामले के रूप में नहीं लिया जा सकता है। पार्टी अदालत से यह नहीं पूछ सकती है कि वह विपक्षी/प्रतिपक्षी को प्रतिस्थापित सेवा द्वारा सेवा देना चाहती है। अदालतों ने इस तरह के आवेदन को दायर करने की प्रथा को खारिज कर दिया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रतिस्थापित सेवा की अनुमति तब तक नहीं है जब तक कि अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचने के कारणों को दर्ज नहीं करती है कि विपक्षी/प्रतिपक्षी को सामान्य तरीके से सेवा देना संभव नहीं है।

19. तेहारूनचंद (उपरोक्त) में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने आदेश V नियम 20 सी.पी.सी. के तहत समन तामील पर विचार करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया: -

"संहिता के आदेश V नियम 20 के अंतर्गत समन जारी करने से पूर्व न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना आवश्यक है कि प्रतिपक्षी समन की तामील से बचने के उद्देश्य से छिप रहा है अथवा अपने स्थान से हट गया है, या किसी अन्य कारण से समन की तामील सामान्य प्रक्रिया से नहीं की जा सकती। ऐसी संतुष्टि प्राप्त करने से पूर्व न्यायालय को समन की तामील के लिए पूर्व में किए गए प्रयासों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रकरण पर सावधानीपूर्वक विचार करना होगा। इस संबंध में केवल वादी द्वारा किया गया कथन, जिससे संहिता के आदेश V नियम 20 के प्रावधानों को लागू किया जा सके, पर्याप्त नहीं होगा। केवल तभी जब न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर इस निष्कर्ष से संतुष्ट हो कि यह विश्वास करने का कारण है कि प्रतिपक्षी समन की तामील से बचने के उद्देश्य से छिप रहा है अथवा किसी अन्य कारण से समन



की तामील सामान्य रीति से नहीं की जा सकती, तभी न्यायालय संहिता के आदेश V नियम 20 के अंतर्गत समन की तामील का आदेश देने के लिए अधिकृत होगा।"

20. के. राजा (उपरोक्त) के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने माना है कि संहिता के आदेश V नियम 17 और आदेश V नियम 20 के प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए। यह माना गया कि आदेश V नियम 17 में निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किए बिना, संहिता के आदेश V नियम 20 के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है।

21. इसी तरह, वीरेंद्र कुमार सोंधी बनाम सुदेश कुमार सूरी और अन्य 2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन एमपी 1304 के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने निम्नानुसार निर्णय दिया: -

"14. हालांकि, प्रतिस्थापित सेवा को नियमित तरीके से आदेश नहीं दिया जा सकता है। सी.पी.सी. के आदेश 5 नियम 20 के प्रावधान का सहारा लेने से पहले, न्यायालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपनी संतुष्टि दर्ज करे कि प्रतिपक्षी सेवा से बचने के उद्देश्य से रास्ते से बाहर रह रहा था और समन को सामान्य तरीके से तामील नहीं किया जा सकता था।

22. श्रीमती पायल अशोक कुमार जिंदल (उपरोक्त) के मामले में, जहां प्रतिपक्षी पति द्वारा तलाक के लिए दायर वैवाहिक याचिका में, अपीलकर्ता को भेजे गए पंजीकृत नोटिस को डाक समर्थन के साथ लौटा दिया गया था कि वह दिए गए पते पर नहीं पाई जा सकती थी, ने माना है कि: -

"..... अभिलेखों पर इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अपीलकर्ता ने नोटिस प्राप्त करने से इनकार कर दिया। पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गए नोटिस वापस प्राप्त होने के बाद, फैमिली न्यायालय ने न्यायालय की प्रक्रिया के माध्यम से अपीलकर्ता की सेवा करने का कोई प्रयास नहीं किया। इन परिस्थितियों में, समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से स्थानापन्न सेवा का सहारा लेना उचित नहीं था। इसलिए, हमारा विचार है कि पारिवारिक न्यायालय के समक्ष वैवाहिक याचिका में अपीलकर्ता की अनुपस्थिति के लिए पर्याप्त कारण था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



23. श्रीमती यल्लावा (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपक्षी पत्नी के खिलाफ पारित तलाक की एकपक्षीय डिक्री को रद्द करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए इस बात पर विचार किया कि क्या वैवाहिक कार्यवाही में, पत्नी पर सेवा पर्याप्त थी, निम्नानुसार अवधारित किया गया था: -

"प्रतिपक्षी के अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत करने में भी उचित ठहराया कि अवर न्यायालय आदेश V नियम 12, 15 और 17 सी.पी.सी. द्वारा निर्धारित सामान्य प्रक्रिया द्वारा प्रतिपक्षी की सेवा के लिए कदम उठाए बिना प्रतिस्थापित सेवा के लिए आवेदन को लगभग स्वचालित रूप से स्वीकार नहीं कर सकती थी। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्रतिस्थापित सेवा को अंतिम उपाय के रूप में सहारा लिया जाना चाहिए जब प्रतिपक्षी को सामान्य तरीके से सेवा नहीं दी जा सकती है और अदालत संतुष्ट है कि यह मानने का कारण है कि प्रतिपक्षी सेवा से बचने के उद्देश्य से रास्ते से बाहर रह रहा है, या किसी अन्य कारण से समन सामान्य तरीके से नहीं तामील किया जा सकता है। प्रस्तुत मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग स्वचालित रूप से प्रतिस्थापित सेवा की प्रक्रिया का सहारा लिया गया था।

24. स्मृति पहाड़िया बनाम उच्चतम न्यायालय ने संजय पहाड़िया (2009)13 एस.सी.सी. 338 (3 न्यायाधीशों द्वारा), अपीलकर्ता पत्नी को दी गई एकपक्षीय तलाक डिक्री को रद्द करते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए, निम्नानुसार अवधारित किया गया: -

"12..... सेवा वापसी को देखते हुए, न्यायालय ने पाया कि सेवा उचित नहीं थी और न्यायालय भी क्रियर के समर्थन से संतुष्ट नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में, सी.पी.सी. के आदेश 5 नियम 20 के तहत प्रतिस्थापित सेवा के लिए अपीलकर्ता-पत्नी की प्रार्थना पर न्यायालय का निर्देश उचित नहीं है। आदेश 5 नियम 20 के तहत प्रतिस्थापित सेवा के लिए निर्देश केवल तभी पारित किया जा सकता है जब न्यायालय संतुष्ट हो कि यह मानने का कारण है कि प्रतिपक्षी सेवा से बचने के उद्देश्य से रास्ते से हट रहा है, या किसी अन्य कारण से समन सामान्य तरीके से नहीं तामील किया जा सकता है।

13. इस मामले के तथ्यों, न्यायालय को ऐसी कोई संतुष्टि नहीं थी, और न ही हो सकती थी क्योंकि न्यायालय ने पाया कि सेवा उचित नहीं थी। यदि सेवा उचित नहीं है,

तो न्यायालय को सामान्य तरीके से एक और तमीला का निर्देश देना चाहिए था और प्रतिस्थापित सेवा को प्रभावित करने के लिए अपीलकर्ता-पत्नी की याचिका को स्वीकार नहीं करना चाहिए था। प्रतिस्थापित सेवा की मांग करने वाली पत्नी के हलफनामे से, यह स्पष्ट है कि प्रतिपक्षी-पति के नौकर ने अपने अधिवक्ता के क्लर्क को सूचित किया कि प्रतिपक्षी-पति बॉम्बे से बाहर है और लगभग दो सप्ताह के लिए बाहर रहेगा। हालांकि, अपीलकर्ता-पत्नी ने दावा किया कि प्रतिपक्षी-पति शहर में था और चोरी कर रहा था। लेकिन सेवा वापसी को देखकर न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा कि पति सेवा से बच रहा था। इसलिए, न्यायालय अपनी संतुष्टि के अभाव में कि पति सेवा से बच रहा है, संहिता के आदेश 5 नियम 20 के तहत सेवा को निर्देशित नहीं कर सकता है।

25. मेसर्स नीरजा रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम मेसर्स नीरजा रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड एलआर (2018) 2 एस.सी.सी. 649 (3 न्यायाधीशों द्वारा) के माध्यम से जंगलू (मृत) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में सुनवाई की। अपीलकर्ता के पक्ष में दिए गए विशिष्ट प्रदर्शन के एकपक्षीय डिक्री को रद्द करते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए, निम्नानुसार अवधारित किया गया: -

"16. जैसा कि बेलीफ की रिपोर्ट से संकेत मिलता है, वह प्रतिपक्षी को उस पते पर खोजने में असमर्थ था जिसका उल्लेख समन में किया गया था। बेलीफ की रिपोर्ट से यह संकेत नहीं मिलता है कि समन घर के एक विशिष्ट हिस्से पर, समन में उल्लिखित पते पर चिपकाया गया था। आदेश V नियम 17 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ था। जब आदेश V नियम 20 के तहत विचारण न्यायालय के समक्ष स्थानापन्न सेवा के लिए आवेदन दायर किया गया था, तो 2 सितंबर 2011 को एक गुप्त आदेश पारित किया गया था। आदेश V नियम 20 के लिए न्यायालय को संतुष्ट होने की आवश्यकता है कि या तो यह मानने का कारण है कि प्रतिपक्षी सेवा से बचने के उद्देश्य से रास्ते से बाहर रह रहा है या किसी अन्य कारण से, समन सामान्य तरीके से नहीं तामील किया जा सकता है। प्रतिस्थापित सेवा सेवा के सामान्य मोड के लिए एक अपवाद है। न्यायालय को आदेश V नियम 20 की आवश्यकताओं पर अपना ध्यान देना चाहिए और उसके आदेश में निहित प्रावधानों पर उचित विचार करना चाहिए। जाहिर है कि



विचारण न्यायालय आदेश V नियम 20 की आवश्यकताओं पर अपना ध्यान लगाने में विफल रहा और एक यांत्रिक आदेश पारित किया। इसके अलावा, जैसा कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा देखा गया है, विचारण न्यायाधीश ने दीवानी न्यायालयों और उसके अधीनस्थ अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अपने अपीलीय स्थल पर जारी सिविल मैनुअल के अध्याय III में निहित प्रावधानों की अनदेखी की.....

17. यह निवेदन कि आदेश V नियम 20 के तहत, अदालत के घर और उस घर पर समन की एक प्रति चिपकाना आवश्यक नहीं था, जहां प्रतिपक्षी को अंतिम बार रहने के लिए जाना जाता है, एक बार जब न्यायालय ने समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा सेवा का निर्देश दिया था, तो वास्तव में सवाल उठता है। आदेश V नियम 17 में निर्धारित प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लंघन था, यहां तक कि उससे पहले भी। इसके अलावा, न्यायालय का आदेश प्रावधान में निर्धारित संतुष्टि की आवश्यकता के लिए दिमाग के उचित आवेदन का संकेत नहीं देता है। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में उचित था कि विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे में एकपक्षीय निर्णय और आदेश को रद्द किया जाना था।

इस न्यायालय द्वारा निष्कर्ष

26. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित उपरोक्त कानून से, यह स्पष्ट है कि संहिता के आदेश V नियम 20 के तहत प्रतिस्थापित सेवा, सेवा के सामान्य तरीके का अपवाद है और इसे न्यायालय द्वारा केवल तभी आदेश दिया जा सकता है जब, यह विश्वास का हो, अभिलेखों पर सामग्री के आधार पर कि प्रतिपक्षी सेवा से बचने के उद्देश्य से रास्ते से बाहर रह रहा है या किसी अन्य कारण से, समन को सामान्य तरीके से तामील नहीं किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट है कि न्यायालय को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर अपना ध्यान लगाना होगा और फिर उसे अपनी संतुष्टि दर्ज करनी होगी कि प्रतिपक्षी पर सेवा सामान्य मोड से संभव नहीं है और उसके बाद ही, वादी/अपीलकर्ता को स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा प्रतिस्थापित सेवा को प्रभावित करने की अनुमति दी जा सकती है।

27. यह भी स्पष्ट है कि न्यायालय को सम्मन की तामील के लिए किए गए पहले के प्रयासों



की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और केवल तभी जब न्यायालय अभिलेखों पर सामग्री से संतुष्ट हो, तो यह मानने का कारण है कि प्रतिपक्षी सेवा से बचने के उद्देश्य से रास्ते से बाहर रह रहा है, या किसी अन्य कारण से, समन को सामान्य तरीके से नहीं तामील किया जा सकता है, न्यायालय संहिता के आदेश V नियम 20 के तहत समन की तमीला का आदेश देने का हकदार होगा।

28. यह भी स्पष्ट है कि अभिलेखों पर साक्ष्य से न्यायालय द्वारा इस बात पर विचार किया जाना है कि विपक्षी/प्रतिपक्षी पर कितनी बार पंजीकृत पावती के कारण (एडी) नोटिस भेजे गए थे; उन अवितरित नोटिसों पर डाक समर्थन क्या किया गया था; देय पावती (एडी) प्राप्त हुई थी या नहीं; क्या प्रक्रिया सर्वर सम्मन की सेवा के लिए विपक्षी/प्रतिपक्षी के निवास/प्रतिष्ठान पर गया था; कितनी बार प्रक्रिया सर्वर विपक्षी/प्रतिपक्षी के निवास/प्रतिष्ठान में गया; जो विपक्षी/प्रतिपक्षी के निवास/प्रतिष्ठान में उपस्थित था; क्या विपक्षी/प्रतिपक्षी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित था जिसने समन प्राप्त करने से इनकार कर दिया था या क्या उसके परिवार के सदस्य/नौकर/कर्मचारी मौजूद थे, जिन्होंने उसकी अनुपस्थिति में समन प्राप्त करने से इनकार कर दिया था; क्या इस तरह के इनकार के 2 गवाहों को नोट किया गया था और उनके हस्ताक्षरित बयान को प्रोसेस सर्वर द्वारा अपनी रिपोर्ट में विधिवत दर्ज किया गया था ताकि उनके कथन को साबित किया जा सके कि वह विपक्षी/प्रतिपक्षी के निवास/प्रतिष्ठान में गए थे, लेकिन वह उपस्थित नहीं थे या वह उपस्थित थे, लेकिन वह जानबूझकर समन प्राप्त करने में विफल रहा।

29. यह भी स्पष्ट है कि जब प्रतिपक्षी/उत्तरदाता न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता की सीमा के बाहर निवास करता है, तब आदेश V नियम 21 सी.पी.सी. के अनुसार उसकी तामील उस न्यायालय के माध्यम से भी की जा सकती है, जिसकी अधिकारिता के अंतर्गत वह निवास करता है अथवा अपना व्यवसाय संचालित करता है।

30. यह भी स्पष्ट है कि आदेश V नियम 17 सी.पी.सी. के अनुसार, यदि विपक्षी/प्रतिपक्षी अपने निवास/प्रतिष्ठान में नहीं पाया जाता है या सम्मन स्वीकार करने से इनकार करता है, तो प्रक्रिया सर्वर सम्मन की प्रति बाहरी दरवाजे या घर के किसी अन्य विशिष्ट हिस्से पर चिपका देगा जिसमें वह आमतौर पर रहता है या व्यवसाय करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है, और फिर मूल समन को जारीकर्ता न्यायालय को वापस कर देगा, उसकी रिपोर्ट

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के साथ कि उसने प्रति और जिन परिस्थितियों में उसने ऐसा किया था, और उन व्यक्तियों (यदि कोई हो) का नाम और पता जिनके द्वारा घर की पहचान की गई थी और जिनकी उपस्थिति में प्रति चिपकाई गई थी।

31. अपीलीय न्यायालय के अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभिलेखों पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है कि कितनी बार और कब एडी के साथ पंजीकृत नोटिस या प्रोसेस सर्वर के माध्यम से समन प्रतिपक्षी/अपीलकर्ता सुभाष चंद गुप्ता को भेजे गए थे; उनका भाग्य क्या था; चाहे वे वितरित किए गए हों या नहीं; क्या उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया था; प्रक्रिया सर्वर की कोई रिपोर्ट नहीं है कि वह अपीलकर्ता के निवास पर गया था जो उपस्थित नहीं पाया गया था या उसने समन स्वीकार करने से इनकार कर दिया था; यह साबित करने के लिए अभिलेखों पर कोई सबूत नहीं है कि उसे भेजे गए पंजीकृत एडी नोटिस बिना डिलीवर किए वापस कर दिए गए थे; अभिलेखों पर कोई डाक विज्ञापन उपलब्ध नहीं है; यह साबित करने के लिए कोई डाक पंजीकरण रसीद अभिलेखों पर उपलब्ध नहीं है कि प्रतिपक्षी/अपीलकर्ता को कभी पंजीकृत नोटिस भेजे गए थे। यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि प्रक्रिया सर्वर अपीलकर्ता के घर गया था और चूंकि समन तामील नहीं किया गया था या मना नहीं किया गया था, इसलिए उसने गवाहों के नाम और पते के साथ अपने घर के बाहरी दरवाजे या विशिष्ट हिस्से पर सम्मन की प्रति चिपका दी, जिन्होंने उसके घर की पहचान की और किसकी उपस्थिति में, समन की प्रति चिपका दी गई थी। यह स्पष्ट है कि, वास्तव में, आदेश V नियम 17 सी.पी.सी. के अनिवार्य प्रावधानों का कोई अनुपालन नहीं है।

32. यह भी स्पष्ट है कि प्रतिपक्षी/अपीलकर्ता सुभाष चंद गुप्ता शाहदरा, दिल्ली में रहता है, जो गाजियाबाद न्यायालय के स्थानीय अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जहां अपीलीय न्यायालय स्थित था, इस प्रकार, गाजियाबाद न्यायालय आदेश V नियम 21 सी.पी.सी. के अनुसार न्यायालय के माध्यम से सेवा को प्रभावित करने के लिए सक्षम दिल्ली न्यायालय को समन भेज सकता था, लेकिन अपीलीय न्यायालय द्वारा इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया था जो बहुत आश्चर्य की बात है।

33. अभिलेखों के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि सीए संख्या-146 वर्ष 2011 को जिला न्यायाधीश गाजियाबाद द्वारा 16.9.2011 को सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया था, और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपीलकर्ताओं को 7 दिनों के भीतर कदम उठाने का निर्देश दिया गया था और अगली तारीख 15.11.2011 निर्धारित की गई थी। 15.11.2011 को, अपील को सुनवाई के लिए ए.डी.जे. न्यायालय संख्या-13, गाजियाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया और अगली तारीख 28.11.2011 निर्धारित की गई। 28.11.2011 को, अपीलकर्ताओं ने प्रकाशन के माध्यम से सेवा को प्रभावित करने के लिए आवेदन 19-सी2 के साथ पंजीकृत पोस्ट एडी के माध्यम से सेवा को प्रभावित करने के लिए एक आवेदन 17-सी2 दायर किया। यह स्पष्ट है कि दोनों आवेदनों को अपीलकर्ताओं द्वारा एक साथ स्थानांतरित किया गया था।

34. अभिलेखों से पता चलता है कि 30.11.2011 को, अपीलीय अदालत ने वादी-अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और इस निवेदन पर विचार करने के बाद कि वाद के लंबित रहने के दौरान विवादित संपत्ति को प्रतिपक्षी संख्या-1-3 द्वारा प्रतिपक्षी संख्या-4 को बेच दिया गया है, इसलिए प्रतिपक्षी संख्या-1 "3 ने रुचि खो दी है, प्रतिपक्षी संख्या-4 जानबूझकर अपील में उपस्थित नहीं हो रहा था, जबकि यह दावा किया गया था कि उन्हें अपील की जानकारी थी, जो विवादित संपत्ति को बेचने की जल्दी में था, अपीलीय अदालत ने अपीलकर्ता अजय कुमार शर्मा के हलफनामे (पेपर संख्या-20-सी) पर विश्वास करते हुए, आवेदन 19-सी 2 की अनुमति दी और स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से सभी प्रतिपक्षियों को प्रतिस्थापित सेवा की अनुमति दी। अपीलीय अदालत ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि पहले प्रतिपक्षियों को नोटिस भेजे गए थे, जो अप्राप्य रहे, इसलिए, अपीलकर्ताओं को प्रतिस्थापित सेवा को प्रभावित करने की अनुमति दी गई। यह स्पष्ट है कि अपीलीय अदालत ने पंजीकृत पोस्ट एडी के माध्यम से सेवा को प्रभावित करने की अनुमति के लिए वादी-अपीलकर्ता आवेदन 17-सी2 पर कोई आदेश पारित नहीं किया।

35. अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि 30.11.2011 से पहले और उसके बाद भी, दीवानी अपील के लंबित रहने के दौरान, पंजीकृत पोस्ट एडी के माध्यम से नोटिस प्रतिपक्षियों को कभी नहीं भेजे गए थे, उनकी सेवा और इनकार के बारे में क्या कहना है। अपील के लंबित रहने के दौरान भी, प्रोसेस सर्वर के माध्यम से प्रतिपक्षीगण को उन पर सेवा लागू करने के लिए कोई समन नहीं भेजा गया था। प्रक्रिया सर्वर की कोई रिपोर्ट अभिलेखों पर उपलब्ध नहीं है। अभिलेखों पर कोई अवितरित पंजीकृत पत्र या पंजीकृत डाक रसीद उपलब्ध नहीं है। अपीलकर्ताओं ने अपीलीय अदालत के समक्ष आवेदन 17-सी2 पेश किया, जिसमें पंजीकृत पोस्ट



एडी के माध्यम से प्रतिपक्षियों पर सेवा प्रभावित करने की अनुमति मांगी गई, जिसे अपीलीय अदालत द्वारा कभी भी निपटाया नहीं गया था, यह स्वयं साबित करता है कि, प्रतिपक्षियों पर सेवा को प्रभावित करने के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा इस पद्धति को कभी नहीं अपनाया गया था। यह साबित करने के लिए अभिलेखों पर कोई दस्तावेजी सबूत नहीं था कि प्रतिपक्षियों को भेजे गए पंजीकृत नोटिस बिना डिलीवर किए वापस कर दिए गए थे, जो जानबूझकर उनके द्वारा प्राप्त नहीं किए गए थे, या प्रोसेस सर्वर के माध्यम से भेजे गए समन जानबूझकर उनके द्वारा प्राप्त नहीं किए गए थे, लेकिन फिर भी, अपीलीय अदालत ने दिनांक 30.11.2011 के आदेश में निष्कर्ष निकाला कि प्रतिपक्षियों को पहले भेजे गए नोटिस जारी नहीं किए गए थे। जबकि, उस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अभिलेखों पर कोई दस्तावेजी सबूत नहीं था।

36. यह स्पष्ट है कि अपीलीय न्यायालय आदेश V नियम 20 सी.पी.सी. के तहत प्रतिस्थापित सेवा की अनुमति देने से पहले, इस बात पर विचार करने में विफल रहा है कि प्रक्रिया सर्वर के माध्यम से कोई पंजीकृत नोटिस या सम्मन कभी भी अपील में प्रतिपक्षियों को नहीं भेजा गया था, पहली जगह में, प्रतिपक्षियों पर प्रतिस्थापित सेवा की अनुमति कभी नहीं दी जानी चाहिए थी। यह साबित करने के लिए अभिलेखों पर कोई सामग्री नहीं थी कि प्रतिपक्षी सेवा से बच रहे थे या सामान्य मोड के माध्यम से सेवा को प्रभावित नहीं किया जा सकता था और वे अपील के लंबित होने के बारे में जानते थे। आदेश V नियम 17 सी.पी.सी. के अनिवार्य प्रावधानों का अपीलकर्ताओं द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में, अपीलीय अदालत निश्चित रूप से वादी-अपीलकर्ताओं को प्रतिपक्षी - दीवानी अपील में प्रतिपक्षी पर प्रतिस्थापित सेवा को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दे सकती थी।

37. उपरोक्त परिस्थितियों में अपीलीय न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि प्रतिपक्षियों पर प्रकाशन द्वारा सेवा पर्याप्त थी, जो उपस्थित नहीं थे, इसलिए 16.2.2012 को दीवानी अपील की सुनवाई के लिए आगे बढ़े और परिणामस्वरूप, ओ.एस. संख्या-544 वर्ष 1997 के अभिलेखों को रिकॉर्ड रूम से मंगाया गया।

38. अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि अपीलीय न्यायालय ने 19.4.2012 को चिंता के साथ नोट किया कि प्रतिपक्षियों पर सेवा को प्रकाशन द्वारा पर्याप्त माना गया था, लेकिन अभिलेखों पर, कोई पावती देय (एडी) उपलब्ध नहीं थी। यह भी नोट किया गया कि इस बात का भी कोई सबूत नहीं था कि अधिवक्ता को नोटिस दिया गया है, जो विचारण न्यायालय में



विपक्षी/प्रतिपक्षियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इन परिस्थितियों में, अपीलीय न्यायालय की राय थी कि गुण-दोष के आधार पर अपील की सुनवाई के लिए यह आवश्यक था कि विपक्षी/प्रतिपक्षियों के अधिवक्ता को नोटिस जारी किए जाएं और इसके लिए अपीलकर्ताओं को कदम उठाने के लिए 7 दिन का समय दिया गया और कार्यालय को प्रक्रिया जारी करने का निर्देश दिया गया। 23.7.2012 को, अपीलीय अदालत ने नोट किया कि प्रतिपक्षियों को पहले ही नोटिस भेजे जा चुके हैं, लेकिन, अभिलेखों से यह पता नहीं चलता है कि विपक्षी/प्रतिपक्षियों के अधिवक्ता को कोई नोटिस दिया गया था, जो विचारण न्यायालय के समक्ष उनकी ओर से पेश हो रहे थे।

39. यह स्पष्ट है कि अपीलीय न्यायालय अपनी संतुष्टि दर्ज करने में विफल रहा है, कि सेवा विपक्षी/प्रतिपक्षियों के अधिवक्ता पर पर्याप्त थी, जो पहले विचारण न्यायालय के समक्ष मूल मुकदमे की कार्यवाही में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। किसी भी दस्तावेजी सबूत के अभाव में, यह नहीं माना जा सकता है कि विपक्षी/प्रतिपक्षियों के अधिवक्ता को अपीलीय कार्यवाही के बारे में पता था, जो जानबूझकर अपीलीय अदालत के समक्ष पेश होने में विफल रहे।

40. अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा आदेश 41 नियम 21 सी.पी.सी. के तहत प्रतिपक्षी/अपीलकर्ता आवेदन 4-सी को खारिज करते हुए निष्कर्ष निकाला है कि प्रतिपक्षी को कई बार नोटिस और समन भेजे गए थे, चूंकि पता गलत नहीं था, इसलिए यह माना गया था कि उन्हें प्रतिपक्षी को विधिवत सेवा दी गई थी। यह भी माना गया था कि जिस अखबार में प्रतिपक्षी पर प्रतिस्थापित सेवा की गई थी, उसकी प्रति भी प्रतिपक्षी को प्राप्त हुई होगी। अपीलीय अदालत ने आगे निष्कर्ष निकाला कि प्रतिपक्षी के आचरण से यह स्पष्ट था कि, अपीलीय अदालत ने डिक्री के 30 दिनों के भीतर एकपक्षीय डिक्री पारित करने के तुरंत बाद वह पेश हुआ, जिसने साबित किया कि प्रतिपक्षी/अपीलकर्ता हमेशा अपीलीय अदालत की कार्यवाही से अवगत रहता था लेकिन वह जानबूझकर इसके सामने पेश नहीं हुआ।

41. अपीलीय न्यायालय का उपरोक्त तर्क अभिलेखों पर किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है, जो कल्पना की एक कल्पना है, जो कानूनी रूप से अस्थिर है। यह स्पष्ट है कि उपरोक्त निष्कर्ष विकृत है, जिसे इस न्यायालय द्वारा अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए रद्द करने की आवश्यकता है। यह साबित हो गया है कि अपीलीय अदालत के लिए प्रतिपक्षियों पर प्रतिस्थापित सेवा की अनुमति देने और अपील को एकपक्षीय सुनवाई करने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का कोई आधार नहीं था। प्रतिपक्षी/अपीलकर्ता के लिए अपीलीय अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं होने का पर्याप्त कारण था क्योंकि समन तामील करना उसके लिए पर्याप्त नहीं था। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि वादी के मूल वाद को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रतिपक्षियों को गुण-दोष के आधार पर अपील करने का अवसर दिए बिना, अवैध रूप से एकपक्षीय रूप से अनुमति दी गई है।

42. उपरोक्त कारणों से, प्रस्तुत अपील की अनुमति दी जाती है। प्रकीर्ण मामला संख्या-71 वर्ष 2019 में पारित दिनांक 23.5.2024 के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है। प्रतिपक्षी/अपीलकर्ता आवेदन 4-सी और विविध मामला संख्या-71 वर्ष 2019, की अनुमति दी जाती है। नतीजतन, दीवानी अपील संख्या-146 वर्ष 2011 में पारित 17.7.2019 के एकपक्षीय निर्णय और डिक्री को रद्द किया जाता है और दीवानी अपील को उसकी मूल संख्या पर बहाल किया जाता है।

43. प्रथम अपीलीय न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह सिविल अपील संख्या 146 वर्ष 2011 की गुण-दोष के आधार पर पुनः सुनवाई कर, दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, विधि के अनुसार इस आदेश की प्रमाणित प्रति उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 4 माह की अवधि के भीतर उसका नवीन निर्णय पारित करे तथा किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन प्रदान न करे।

44. पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वे गुण-दोष के आधार पर अपील के निपटान तक विवादित संपत्ति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखें।

दिनांक: 11.02.2026 / जितेंद्र / हिमांशु / मयंक

(न्यायमूर्ति संदीप जैन)